कुरुक्षेत्र

उद्योग कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु कार्ययोजना

संदर्भ

- अंतरिम बजट 2024 का फोकस गरीब, महिला, युवा और किसानों पर था। जबकि हाल के बजट में रोज़गार, कौशल विकास, एम.एस.एम.ई. और मध्यम वर्ग पर ज़ोर दिया गया है।

केंद्रीय बजट 2024–25 प्राथमिकताएँ

- रोज़गार और कौशल विकास
- समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
- नवाचार, अनुसंधान और विकास
- कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
- विनिर्माण और सेवाएँ
- शहरी विकास
- ऊर्जा सुरक्षा
- बुनियादी अवसंरचना
- भावी पीढ़ी के सुधार

भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश

- देश में 18-35 वर्ष की आयु के 60 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं जिनमें से 65% 35 वर्ष से कम आयु के हैं।
- भारत की कार्यशील आयु की आबादी वर्ष 2041 तक बढ़ती रहेगी।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24 के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ते

कार्यबल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में वर्ष 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख रोज़गार सृजित करने की ज़रूरत है।

श्रम कार्यबल भागीदारी

- श्रम कार्यबल की भागीदारी वर्ष 2017–18 में 49.8% से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 57.9% हो गई है।
- महिलाओं की भागीदारी वर्ष 2017–18 में 23.3% थी जो बढ़कर वर्ष 2022–23 में 37% हो गई है।
- भारत में 45% से अधिक कार्यबल कृषि में, 11.4% विनिर्माण में, 28.9% सेवाओं में और 13% निर्माण कार्यों में संलग्न हैं।
- भारत में युवा बेरोज़गारी दर वर्ष 2017–18 में 17.8% से घटकर वर्ष 2022–23 में 10% हो गई है।
- वस्तुत: शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोज़गार की स्थिति में सुधार हुआ है।
- एक अनुमान के अनुसार, 51.25% युवा रोज़गार के लिए योग्य माने गए हैं। गौरतलब है कि पिछले दशक में यह प्रतिशत लगभग 34% था।

कुशल कार्यबल के लिए प्रयास

प्रधानमंत्री पैकेज

- प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में, पाँच प्रमुख योजनाओं और पहलों की घोषणा की गई है जिन्हें 2 लाख करोड़ रुपए के बड़े केंद्रीय परिव्यय द्वारा सहयोग किया गया है।
- यह पैकेज पाँच वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को रोज़गार, कौशल विकास और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करेगा और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को अपग्रेड करेगा।

- इसका उद्देश्य उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम सामग्री और डिज़ाइन के साथ कौशल विकास के परिणाम और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा, आई.टी.आई. को हब-एंड-स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड करने की बात कही गई है।

कौशल विकास को बढ़ावा

- कुल बजट आवंटन के संदर्भ में कौशल भारत कार्यक्रम के लिए 55% की वृद्धि हुई है। इसमें तीन योजनाएँ शामिल हैं-
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0)
- प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (PM-NAPS)
- जन शिक्षण संस्थान (JSS)
- वित्त वर्ष 2025 के लिए योजनाओं को 12,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
- इनमें से 10,000 करोड़ रुपए रोज़गार से जुड़ी तीन प्रोत्साहन (ELI) योजनाओं के लिए श्रम मंत्रालय को आवंटित किए गए हैं और 2,000 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को दिए गए हैं।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) ने वर्ष 2015 से 1.42 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है।
- इस योजना के तहत 1,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों को कौशल भारत केंद्रों के रूप में एकीकृत किया गया है।
- बजट में अगले पाँच वर्षों में 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसरों की भी घोषणा की गई है जिसमें 5,000 रुपए प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।

मॉडल कौशल ऋण योजना

- मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत सरकार-समर्थित गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के माध्यम से सालाना 25,000 छात्र लाभान्वित होंगे।
- इस योजना के पात्र व्यक्तियों को घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- साथ ही, ई-वाउचर के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 1 लाख छात्रों के लिए 3% की वार्षिक ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी।

अनौपचारिक कार्यबल पर फोकस

स्ट्रीट वेंडर

- बेहतर कारोबारी माहौल और सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत भारतीय स्ट्रीट मार्केट की स्थापना की जाएगी।
- अगले पाँच वर्षों के लिए चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक 'हाट' अथवा स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहयोग करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई है।

पीएम विश्वकर्मा योजना

- इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2025 के लिए 4,824 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
- यह वित्त वर्ष 2024 (990 करोड़ रुपए) की तुलना में 387.3% की वृद्धि है।
- गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2023–24 से वित्त वर्ष 2027–28 तक इस योजना के लिए वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए है।

पीएम विश्वकर्मा योजना

- इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2023–24 में की थी और सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था।
- **उद्देश्य :** ऐसे कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है जो अपने हाथों और औज़ारों से काम करते हैं।
- **योजना के घटक :**
  - पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और आई.डी. कार्ड
  - कौशल उन्नयन
  - टूल किट प्रोत्साहन
  - ऋण सहायता
  - डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन
  - विपणन सहायता के माध्यम से मान्यता प्रदान करना
- **योजना के तहत 18 पात्र व्यापार हैं-** बढ़ई, नाव निर्माता, कवच निर्माता, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार (पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला, मोची (चर्मकार)/ जूते बनाने वाला/जूता कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॉयर बुनकर, गुड़िया और खिलौने बनाने वाला (पारंपरिक), नाई, माला निर्माता (मालाकार), धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने के जाल निर्माता।

श्रम कल्याण पहल

- बजट में श्रम कल्याण के अंतर्गत, ई-श्रम पोर्टल को अन्य प्लेटफॉर्मों के साथ व्यापक रूप से एकीकृत करना, कौशल आवश्यकताओं, नौकरी की भूमिकाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान की सुविधा प्रदान करना और नौकरी के इच्छुक लोगों को संभावित नियोक्ताओं व कौशल प्रदाताओं से जोड़ना शामिल है।

- श्रम सुविधा और समाधान पोर्टलों के पुनरुद्धार से उद्योग अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाएगा और साथ ही, श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र को बढ़ाया जाएगा।

मनरेगा

- ग्रामीण रोज़गार के लिए फ्लैगशिप योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी, 'मनरेगा' को 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

कृषि और संबद्ध क्षेत्र

- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है।
- इसके अलावा, ग्रामीण बुनियादी ढाँचे सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान किया गया है।
- वस्तुत: 25,000 ग्रामीण बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PM-GSY) के चरण 4 के शुभारंभ की भी घोषणा की गई है।
- यह अप्रत्यक्ष रूप से दूरदराज़ के इलाकों में रोज़गार सृजन को बढ़ावा देगा।

पूंजीगत व्यय

- वित्त वर्ष 2025 में पूंजीगत व्यय में 11% की उल्लेखनीय वृद्धि करके 11.11 लाख करोड़ किया गया है।
- देश के 100 शहरों में 12 औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा।

महिला सशक्तीकरण

- आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24 में देखभाल कार्य को परिभाषित किया गया है और देखभाल को 'कार्य' के रूप में स्वीकार किया गया है।

- वस्तुत: महिला कार्यबल के लिए केयर वर्क का विशेष महत्त्व है जिससे उनके लिए रोज़गार के नए अवसर खुलते हैं।
- महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है।
- सरकार उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाएगी और ऐसे क्रेच स्थापित करेगी जिससे अधिक-से-अधिक महिलाएँ कार्यबल में भाग ले सकें।
- शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS) 14,955 आई.टी.आई. के साथ दीर्घकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है जिससे महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- जन शिक्षण संस्थान (JSS) ने वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2024 तक 26.36 लाख गैर/नव-साक्षर लोगों को प्रशिक्षित किया है। इसमें 82% लाभार्थी महिलाएँ हैं।
- राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) के तहत 32.38 लाख प्रशिक्षुओं को शामिल किया गया है और उद्योग की भागीदारी को बढ़ाया गया है। इससे महिला प्रशिक्षुओं में पर्याप्त वृद्धि हुई है।
- पीएम-सूर्य घर योजना 30 गीगावॉट सौर क्षमता जोड़ने के उद्देश्य से फरवरी 2024 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य सौर मूल्य शृंखला में लगभग 17 लाख नौकरियाँ सृजित करना है।

विकसित भारत की कार्ययोजना का निर्धारण

- पाँच वर्ष की अवधि में 41 लाख युवाओं को कौशल और रोज़गार की सुविधा प्रदान करने वाली पाँच योजनाओं और शिक्षा, रोज़गार एवं कौशल विकास हेतु 1.48 लाख करोड़ रुपए के आवंटन किया गया है।

- वस्तुत: बजट में 'विकसित भारत' के विज़न को साकार करने के लिए आवश्यक उपायों की रूपरेखा तैयार की गई है।
- नीति आयोग के 'विकसित भारत-2047' के लिए दृष्टिकोण पत्र के अनुसार, भारत को 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास करना होगा जो अभी 3.36 ट्रिलियन डॉलर है।
- इसके अलावा, प्रति व्यक्ति आय जो वर्तमान में 2,392 डॉलर प्रति वर्ष है, को बढ़ाकर 18,000 डॉलर प्रति वर्ष करना होगा।
- आयोग के अनुसार, उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण-शहरी आय के अंतर को कम करना और कृषि में शामिल कार्यबल को विनिर्माण में स्थानांतरित करना अनिवार्य है।

ड्डषि हेतु बजट में कल्याण और विकास के बीच संतुलन

संदर्भ

- सरकार ने 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता सूची में कृषि को सबसे ऊपर रखा गया है। बजट 2024–25 में समग्र रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुल आवंटन 6.2 लाख करोड़ है। यह कुल राष्ट्रीय बजट 48.2 लाख करोड़ रुपए का लगभग 13% है।

कुल आवंटित राशि का लेखा-जोखा

- **खाद्य सब्सिडी:** 2,05,250 करोड़, लगभग एक-तिहाई (30%) हिस्सा।
- **उर्वरक सब्सिडी:** 1,64,000 करोड़ रुपए (24%)
- उर्वरक सब्सिडी वित्त वर्ष 2024 के संशोधित अनुमान में 1.88 लाख करोड़ रुपए (13.2%) कम हो गई है।
- हालाँकि, यह अभी भी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के बजट का 97.3% है।

- वर्ष 2022–23 में उर्वरक की खपत 29.84 मिलियन टन (MMT) तक पहुँच गई, जो औसतन 141.2 किग्रा./हे है।
- शेष राशि में मनरेगा (12%) और पीएम किसान योजना (9%)] प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (8%)] पीएम ग्राम सड़क योजना (3%)] क्रेडिट सब्सिडी (3%)] पीएम फसल बीमा योजना (2%) और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (1%) के बीच वितरित किया गया है।
- गौरतलब है कि कृषि अनुसंधान के लिए केवल 1% धनराशि आवंटित की गई है।

कल्याणकारी परियोजनाएँ

- **उन्नत कृषि एवं बागवानी फसल:** जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, किसानों के लिए 32 कृषि एवं बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज देने वाली एवं जलवायु प्रतिरोधी प्रजातियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- प्रधानमंत्री ने 11 अगस्त, 2024 को 61 फसलों की 109 नई किस्में जारी कीं, जिनमें 34 खेती की फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं।
- **जैविक खेती को बल:** बजट 2024–25 में सरकार की योजना अगले दो वर्षों में देश भर के 1 करोड़ किसानों को जैविक खेती से जोड़ने की है, जिन्हें प्रमाणीकरण व प्रमाणन द्वारा समर्थित किया जाएगा।
- इसका क्रियान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा और इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

- **उत्पादन, भंडारण और विपणन सुविधाओं का उन्नयन:** सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी सहित तिलहनों के उत्पादन में 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उत्पादन, भंडारण और विपणन सुविधाओं में सुधार करने की योजना विकसित की जा रही है।
- भारत अभी खाद्य तेल के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है।
- **अभिनव नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय बजट 2024–25 में 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसकी शुरुआत मार्च 2024 में हुई थी।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देना है, ताकि वे उन्हें किसानों को किराये पर दे सकें। इसकी क्रियान्वयन की समय सीमा वर्ष 2023–26 है।
- यह ग्रामीण समुदायों में महिलाओं को सशक्त बनाएगा तथा उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करेगा।
- **झींगा उत्पादन:** भारत दुनिया भर में झींगा के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। देश ने वर्ष 2022–23 में 63969.14 करोड़ रुपए मूल्य के समुद्री भोजन का निर्यात किया।
- निर्यातों में से अधिकांश निर्यात फ्रोज़न झींगा का था, जो मूल्य के हिसाब से 70% और मात्रा के हिसाब से 40% था।
- झींगा उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के प्रयास में झींगा ब्रूडस्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस प्रजनन केंद्रों के नेटवर्क की स्थापना के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा।
- इसके अलावा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) झींगा पालन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए वित्तपोषण में मदद करेगा।

विभिन्न क्षेत्रों में संलग्न कार्यबल और सकल मूल्य वर्धन में योगदान

- वर्ष 2022–23 में, कृषि क्षेत्र में लगभग 46% कार्यबल कार्यरत था और सकल मूल्य वर्धन (GVA) में इसका योगदान 18% था।
- उद्योग क्षेत्र ने 25% कार्यबल को रोज़गार दिया तथा जिसने GVA में 28% का योगदान दिया।
- सेवा क्षेत्र ने 29% कार्यबल को रोज़गार दिया, जिसका जी.वी.ए. में सर्वाधिक 54% का योगदान था।
- उपरोक्त स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र की प्रमुख बाधाओं को दूर करने और समृद्धि को बढ़ाने के लिए सरकार अगले तीन वर्षों के दौरान कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) एग्री स्टैक शुरू करने की योजना बना रही है।
- एग्री स्टैक, एक ओपन सोर्स डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि को आगे बढ़ाना और हितधारकों के लिए डाटा को अधिक सुलभ बनाकर किसानों की आय बढ़ाना है।
- **किसान क्रेडिट कार्ड:** सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाने का प्रस्ताव दिया है। जन समर्थ किसान क्रेडिट कार्ड को पाँच राज्यों में लॉन्च किया जाएगा जिससे इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ेगा।
- के.सी.सी. की स्थापना 1998 में किसानों को उनकी परिसंपत्तियों के आधार पर कार्ड जारी करने के लिए की गई थी। इसका उपयोग विभिन्न कृषि सामग्रियों की आसना खरीद के लिए किया जा सकता है।
- **प्रधानमंत्री-फसल बीमा योजना (PM-FBY):** वर्ष 2024–25 के बजट में पी.एम.एफ.बी.वाई. के लिए 14,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह वर्ष 2023–24 के अनुमान से 3% कम है।

- इस योजना के तहत किसान खरीफ फसलों के लिए 2%] रबी फसलों के लिए 1.5% और कृषि फसलों के लिए 5% का भुगतान करते हैं।
- वर्ष 2020 में इस योजना को किसानों के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया।
- इसका उद्देश्य किसानों को रोपण से पूर्व से लेकर कटाई के बाद तक किसी भी समय उत्पन्न होने वाले जोखिमों के विरुद्ध पर्याप्त बीमा प्रदान करना है।

राष्ट्रीय सहकारी नीति

- सरकार ने सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित और सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। इस नीति का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास और बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसरों का सृजन करना है।
- सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सहयोग नीति विकसित करने के लिए 49 सदस्यीय सरकारी समिति की स्थापना भी की है।
- इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी, कौशल और ज्ञान को संयोजित करने वाले सहयोगात्मक आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना था।

राष्ट्रीय नवाचार कोष

- कृषि ऋण संगठनों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय नवाचार कोष के निर्माण का प्रस्ताव किया गया।
- इस नीति का उद्देश्य बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर पैदा करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विस्तार में तेज़ी लाना है।

निष्कर्ष

- सरकार ने पिछले दस वर्षों में ग्रामीण और कृषि समुदायों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए किए गए प्रयासों की गति को बनाए रखने का निरंतर प्रयास किया है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023–24 के अनुसार, कृषि विकास दर में भारी गिरावट आई है, जो वर्ष 2023–24 में 1.4% रह गई है, जबकि 2022–23 में 4.7% की वृद्धि दर थी।

- इसका मुख्य कारण अल-नीनो के कारण देरी और खराब मानसून के कारण खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट है। अत: हमें अपने किसानों को ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है, जिसके लिए प्रारंभिक उपायों में कृषि में बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी को मज़बूत करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

बजट में भावी पीढ़ी में सुधार

संदर्भ

- आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2025 की भारत की आर्थिक विकास दर 6.5–7% रहने का अनुमान है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने 7% की आर्थिक विकास दर की संभावना व्यक्त की है।
- इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पूर्वानुमान के अनुसार, भारत वित्त वर्ष 2024–25 और वर्ष 2025–26 में विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा और इसकी विकास दर क्रमश: 7% और 6.5% के आसपास हो सकती है।
- यह विकास दर वैश्विक औसत के दोगुनी से भी अधिक है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में उल्लेख किया है कि भारत में विकास को अधिक बढ़ावा देने के लिए भूमि, श्रम, पूंजी व उद्यमिता जैसे उत्पादन के विभिन्न कारकों को शामिल करते हुए भावी पीढ़ी के सुधारों को शुरू करने व उन्हें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है।
- सरकार इस संदर्भ में जल्दी ही एक आर्थिक नीति संबंधी रूपरेखा तैयार कर सकती है।

विभिन्न सुधार

ग्रामीण क्षेत्रों में

- भूमि संबंधी प्रस्तावित कार्रवाई में सभी प्रकार की भूखंडों के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) या भू-आधार का आवंटन, कैडस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण, वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप-विभाजनों का सर्वेक्षण, भूमि रजिस्ट्री की स्थापना और किसानों की रजिस्ट्री से लिंक करना शामिल है।
- **वस्तुत:** उपरोक्त उपाय ऋण प्रवाह और अन्य कृषि सेवाओं को सुविधाजनक बनाएंगे।
- किसानों का डाटाबेस विकसित करने के लिए, कृषि मंत्रालय एक डिजिटल रजिस्ट्री बना रहा है जिसमें 9 करोड़ से अधिक किसानों को एक विशिष्ट आई.डी. प्रदान की जाएगी। ये विशिष्ट आई.डी. भूमि रिकॉर्ड और आधार कार्ड से जुड़ी होगी।
- किसानों का डिजिटल डाटाबेस विकसित करने की कृषि मंत्रालय की पहल कर्नाटक के फल किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली (FRUITS) सॉफ्टवेयर पर आधारित है।
- यह स्वामित्व को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड और राज्य की डिजिटाइज़्ड भूमि रिकॉर्ड प्रणाली का उपयोग करके एकल पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है।

शहरी क्षेत्रों में

- शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) मैपिंग के साथ डिजिटल किया जाएगा।
- संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन, अद्यतनीकरण और कर प्रशासन के लिए एक आई.टी.-आधारित प्रणाली स्थापित की जाएगी। इससे शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा।

श्रम सुधार

- ई-श्रम पोर्टल का अन्य पोर्टलों के साथ व्यापक एकीकरण किया जा रहा है, जो वन-स्टॉप समाधान की सुविधा प्रदान करेगा।
- तेज़ी से बदलते श्रम बाज़ार, कौशल आवश्यकताओं व उपलब्ध रोज़गार भूमिकाओं के लिए ओपन आर्किटेक्चर डाटाबेस और नौकरी के इच्छुक लोगों को संभावित नियोक्ताओं व कौशल प्रदाताओं से जोड़ने के लिए एक प्रणाली इन सेवाओं में शामिल की जाएगी।
- उद्योग और व्यापार हेतु अनुपालन को आसान बनाने के लिए श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को नया रूप दिया जाएगा।

पेंशन सुधार

- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) 'वात्सल्य' के अंतर्गत नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान की योजना शुरू की गई है जिससे उनके वयस्क होने पर इस योजना को सामान्य एन.पी.एस. खाते में आसानी से बदला जा सकेगा।

वित्तीय क्षेत्र में सुधार और निवेश प्रोत्साहन

- अर्थव्यवस्था की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार वित्तीय क्षेत्र के विज़न और कार्यनीति संबंधी दस्तावेज़ लाने पर विचार कर रही है।
- यह दस्तावेज़ अगले पाँच वर्षों के लिए एजेंडा निर्धारित करेगा और सरकार, नियामकों, वित्तीय संस्थानों व बाज़ार सहभागियों के काम का मार्गदर्शन करेगा।
- जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने हेतु जलवायु वित्त के लिए एक टेक्सोनॉमी (वर्गीकरण) विकसित की जाएगी।
- इससे देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं और ग्रीन ट्रांज़िशन की उपलब्धि में सहयोग मिलेगा।
- विमानों और जहाज़ों के पट्टे के वित्तपोषण के लिए एक कुशल व लचीली पद्धति की दिशा में काम करेगी और एक 'वेरिएबल कंपनी संरचना' के माध्यम से निजी इक्विटी के पूल किए गए फंड का उपयोग करेगी।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश व अन्य निवेश के लिए नियमों और विनियमों को सरल बनाया जाएगा और विदेशी निवेश के लिए मुद्रा के रूप में भारतीय रुपए का उपयोग करने के अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रौद्योगिकी को अपनाना और ईज़ ऑफ डूइंग

- 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' को बढ़ाने के लिए सरकार जन विश्वास विधेयक 2.0 पर काम कर रही है।

- वस्तुत: संसद में जुलाई, 2023 में पारित जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2023 के माध्यम से केंद्रीय अधिनियमों में कुल 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है। इस कानून का उद्देश्य आपराधिक प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना है।
- डाटा गवर्नेंस, संग्रहण, प्रसंस्करण और डाटा तथा सांख्यिकी के प्रबंधन में सुधार के लिए, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत स्थापित किए गए विभिन्न क्षेत्रीय डाटाबेस का उपयोग किया जाएगा।

निष्कर्ष

- सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समावेशी विकास को बढ़ावा देने हेतु भूमि, श्रम, पूंजी और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना सहित उत्पादन के कारकों में भावी पीढ़ी के संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत करना चाहती है।